

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *42
जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
1 श्रावण, 1947 (शक)

इंडिया एआई मिशन

***42. श्री बालभद्र माझी:
सुश्री बॉसुरी स्वराज़:**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इंडिया एआई मिशन के उद्देश्यों और उसकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत कुल परिकलित क्षमता कितनी है और इसमें कितने जीपीयू जोड़े गए हैं और इस अवसंरचना से एआई नवोन्मेष में किस प्रकार सहायता मिलती है;
- (ग) डेटासेट की संख्या सहित वर्तमान में प्रदर्शित किए गए "एआईकोशा प्लेटफॉर्म" का उद्देश्य और प्रगति क्या है और स्वदेशी एआई संबंधी समाधान विकसित करने में इससे किस प्रकार सहायता मिलती है;
- (घ) इंडिया एआई फाउंडेशन मॉडल संबंधी पहल के अंतर्गत किस प्रकार के और कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और चयनित स्टार्टअप्स द्वारा किन-किन क्षेत्रों को लक्षित किया गया है; और
- (ङ) इंडिया एआईआई4सी साइबरगार्ड, एआई हैकथॉन के भागीदारी संबंधी अंकड़ों सहित इसके प्रमुख परिणाम क्या हैं तथा विजेता टीमें कौन सी हैं और एआई-संचालित साइबर सुरक्षा को और बढ़ाने में इसकी क्या भूमिका है?

उत्तर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

.....

भारत की एआई रणनीति माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रौद्योगिकी उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के विष्णिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत-केंद्रित चुनौतियों का समाधान करना और सभी भारतीयों के लिए आर्थिक और रोज़गार के अवसर पैदा करना है।

वर्तमान में भारत में एआई पारिस्थितिकी तंत्र:

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध है। यह 250 बिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है और 6 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है।

स्टैनफोर्ड एआई रैंकिंग जैसी वैश्विक रैंकिंग एजेंसी भारत को एआई कौशल, क्षमताओं और एआई उपयोग से जुड़ी नीतियों के मामले में शीर्ष देशों में रखती है। भारत गिटहब एआई परियोजनाओं में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है, जो इसके जीवंत डेवलपर समुदाय को दर्शाता है।

भारत की एआई रणनीति:

भारत की एआई रणनीति का उद्देश्य भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। सरकार ने मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन शुरू किया। यह भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप एक मज़बूत और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए शुरू की गई एक रणनीतिक पहल है।

एआई मिशन के सात स्तंभ इस प्रकार हैं:

1. इंडिया एआई कंप्यूट स्टंभ

- भारतीय स्टार्ट-अप्स और शिक्षा जगत को किफायती लागत पर उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग शक्ति (जीपीयू) उपलब्ध कराना।
- अब तक, 14 सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं से 34,381 जीपीयू ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं।
- भारत सरकार इन जीपीयू को रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है। इन जीपीयू की औसत कीमत लगभग 65 रुपए प्रति जीपीयू प्रति घंटा है। फाउंडेशनल मॉडल प्रशिक्षण में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एच100 जीपीयू की कीमत 92 रुपए प्रति जीपीयू प्रति घंटा है, जो वाणिज्यिक हाइपरस्केलर क्लाउड प्रदाता की तुलना में काफी कम है।

2. इंडिया एआई अनुप्रयोग विकास पहल

- इस स्तंभ का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन और अधिगम की समस्याओं से निपटने के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में भारत की विशिष्ट चुनौतियों के लिए एआई अनुप्रयोग विकसित करना है।
- आज तक 30 (तीस) अनुप्रयोग अनुमोदित किए जा चुके हैं।

- इसके अतिरिक्त, अन्य मंत्रालयों और सरकारी संस्थानों के साथ साझेदारी में क्षेत्र-विशिष्ट हैकथॉन का आयोजन किया गया है।
- उदाहरण: इंडियाएआई ने साइबर सुरक्षा के लिए एआई-संचालित समाधान विकसित करने हेतु गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के सहयोग से साइबरगार्ड एआई हैकथॉन का शुभारंभ किया।

3. एआईकोश

- प्रशिक्षण एआई मॉडलों के लिए बड़े डेटासेट विकसित करना।
- एआईकोश एक ऐसा एकीकृत डेटा प्लेटफॉर्म है जो सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से डेटासेट को एकीकृत करता है।
- मार्च 2025 में लॉन्च किए गए बीटा संस्करण में वर्तमान में 879 से अधिक डेटासेट, 208 एआई मॉडल और 13 से अधिक विकास टूल्किट जैसी विशेषताएं शामिल हैं।
- ये संसाधन डेवलपर्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करते हैं, जिससे उन्हें मॉड्यूल को फिर से बनाने के बजाय कोर एआई कार्यक्षमता पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है।
- उदाहरण: कृषि एआई समाधानों पर काम करने वाली एक टीम किसान कॉल सेंटर के डेटासेट का उपयोग कर सकती है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक किसानों के प्रश्न शामिल हैं। इससे उन्हें अपना मॉडल बनाने और उसे बेहतर करने में मदद मिलती है।
- इस प्लेटफॉर्म को 2,65,000 से अधिक बार देखा गया, इसके 6,000 पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और 13,000 से अधिक संसाधन डाउनलोड किए गए हैं।

4. इंडियाएआई फाउंडेशन मॉडल

- भारतीय डेटासेट और भाषाओं पर प्रशिक्षित भारत के अपने बड़े मल्टीमॉडल मॉडल (एलएमएम) विकसित करना।
- इसका उद्देश्य जनरेटिव एआई के क्षेत्र में संप्रभु क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।
- इंडियाएआई मिशन को 500 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पहले चरण में 4 स्टार्टअप का चयन किया गया है। इनमें सर्वम एआई, सोकेट एआई, ज्ञानी एआई और गण एआई शामिल हैं।

5. इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स

- एआई क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी धारकों की संख्या बढ़ाकर भारत में एआई के क्षेत्र में कुशल पेशेवरों का विकास करना। निम्नलिखित को सहायता प्रदान की जा रही है:
 - 500 पीएचडी फेलो
 - 5,000 स्नातकोत्तर
 - 8,000 स्नातक
- पहले वर्ष में 200 से अधिक छात्रों को फेलोशिप प्राप्त हुई है तथा 26 भागीदार संस्थान पीएचडी छात्रों को ऑनबोर्ड कर रहे हैं।

- इसमें भारत भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है।
- इंडियाएआई ने नाइलिट के सहयोग से देश भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में 27 डेटा लैब चिह्नित किए हैं।
- इसके अलावा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इंडियाएआई डेटा लैब स्थापित करने के लिए 174 आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को नामित किया है।

6. इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग

- एआई स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- मार्च 2025 में स्टेशन एफ (पेरिस) और एचईसी पेरिस के सहयोग से इंडियाएआई स्टार्टअप्स ग्लोबल प्रोग्राम शुरू किया गया। 10 भारतीय एआई स्टार्टअप्स को यूरोपीय बाजार में विस्तार करने में मदद की जा रही है।

7. सुरक्षित और विश्वसनीय एआई

- जिम्मेदारी के साथ एआई को अपनाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत शासन ढांचे के साथ नवाचार को संतुलित करना।
- पहले दौर में, मशीन अनलर्निंग, पूर्वाग्रह शमन, गोपनीयता-संरक्षण, मशीन लर्निंग, व्याख्यात्मकता, लेखापरीक्षा टूल और गवर्नेंस परीक्षण ढांचे जैसे मुद्दों का समाधान करने वाली 8 परियोजनाओं का चयन किया गया है।
- दूसरे दौर में 400 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- इंडियाएआई सुरक्षा संस्थान की स्थापना के लिए साझेदार संस्थानों को ऑनबोर्ड करने हेतु 09 मई 2025 को अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रकाशित की गई।

एआई पर वैश्विक बहस को आकार देना:

- भारत एआई के विकास, उपयोग और सुरक्षा पर वैश्विक बहस को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।
- भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी (जीपीएआई) का संस्थापक अध्यक्ष था।
- भारत जी-20 विज्ञप्ति के दौरान एआई पर आम सहमति बनाने में सफल रहा।
- भारत फरवरी 2026 में एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, स्टार्ट-अप्स, निजी क्षेत्र की कंपनियों और शिक्षाविदों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए काम करेगा।
